डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 अगस्त, 2021, डिस्पेच दिनांक 16 अगस्त, 2021

| वर्ष 65 | अंक 6 | भोपाल | 16 अगस्त, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

किसानों को सम्मान राशि का हस्तांतरण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिली 9वीं किश्त

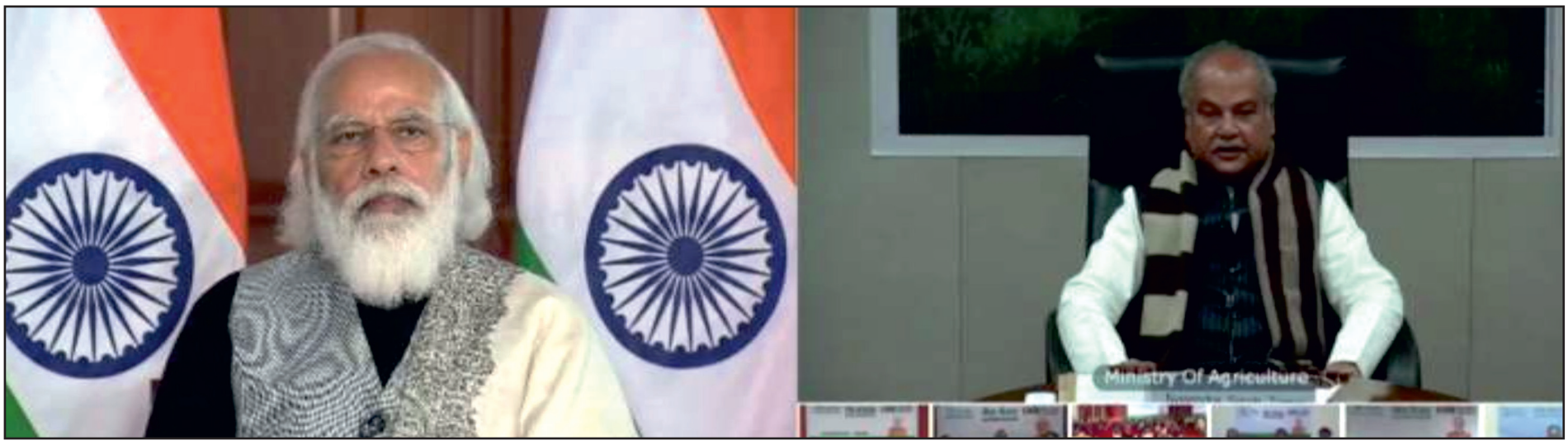

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 9 वीं किश्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से बातचीत करने के साथ राष्ट्र को संबोधित भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि(पीएम-किसान) योजना के तहत, पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रूपए प्रति वर्ष की आर्थिक मदद दी जाती है। 2000 रुपये की 3 किस्तों में प्रत्येक 4 माह में प्रदान किया जाता है। धनराशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप-10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है। इससे जम्मू-कश्मीर में केसर की खेती को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो इसके लिए हमें काम करना है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का संकल्प लिया गया है। आज देश भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है, इस ऐतिहासिक दिन में ये संकल्प हमें ऊर्जा से भर देता है। परिणाम ये हुआ कि बीते 6 साल में देश में दाल के उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पीएम मोदी ने कहा कि देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, 2047 में तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है, जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का लाभ उठा सके. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दिनों से मैं सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा कर रहा हूं। सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, उनका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, ये और बेहतर तरीके से हमें पता चलता है। जनता जनार्दन से डायरेक्ट कनेक्शन का यही लाभ होता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश बीमारू राज्य की पहचान से मुक्त हुआ : प्रधानमंत्री श्री मोदी

गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने से मुझे ताकत मिलती है : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का दसों दिशाओं में विकास हुआ : मुख्यमंत्री श्री चौहान ● प्रदेश के 1 करोड़ 15 लाख परिवारों को नि:शुल्क राशन

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश, बीमारू राज्य की अपनी पहचान से मुक्त हुआ है। मध्यप्रदेश के शहर स्वच्छता और विकास में नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आयोजित अनाज वितरण कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए कहा कि लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को मध्यप्रदेश में योजना में एक साथ अनाज उपलब्ध कराने का बड़ा अभियान चल रहा है।

इस कार्यक्रम ने मुझे गरीबों के बीच बैठकर बात करने का मौका दिया है। इससे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की मुझे ताकत मिलती है। यह दु:खद है कि प्रदेश के कई जिलों में अति वर्षा और बाढ़ से लोगों का जीवन और आजीविका प्रभावित हुई है। केन्द्र सरकार प्रदेश की जनता के साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान और उनकी पूरी टीम राहत और बचाव के हरसंभव कार्य कर रही है। केन्द्र सरकार की ओर से भी सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आयोजित नि:शुल्क राशन वितरण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने योजना के हितग्राही सतना के दिलीप कुमार कोरी, निवाड़ी के चंद्र बदन विश्वकर्मा, होशंगाबाद की माया धुर्वे और बुरहानपुर के राजेंद्र शर्मा से वर्चुअली संवाद भी किया।

25 हजार 435 उचित मूल्य की दुकानों पर हुआ कार्यक्रम

कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की। खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह तथा सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया भी मिंटो हॉल में इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री श्री सुदेश जोशी तथा मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मिलने वाले नियमित राशन के साथ 5 किलो गेहूँ और चावल हितग्राहियों को मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। यह खाद्यान्न राशन थैले में प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के 1 करोड़ 15 लाख परिवार इस खाद्यान्न वितरण से लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम प्रदेश की सभी 25 हजार 435 उचित मूल्य की दुकानों पर आयोजित किया गया।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

नए कृषि सुधार कानून खेती को समृद्धता देने वाले : श्री तोमर

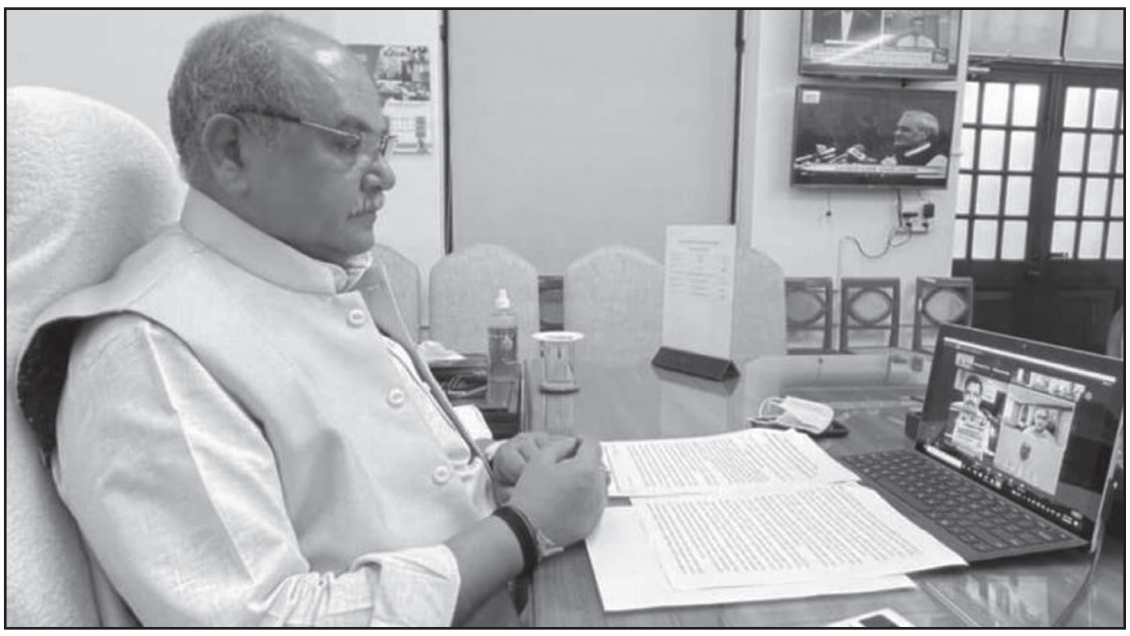

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार गांव-गरीब-किसान-किसानी की प्रगति के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। इस दिशा में कई योजनाएं प्रारंभ की गई है। देशभर में गांव-गांव अधोसंरचना विकसित करने के लिए एक लाख करोड़ रूपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित आत्मनिर्भर भारत अभियान में कुल डेढ़ लाख करोड़ रूपए से अधिक के पैकेज शुरू किए गए हैं। इसी तरह, 6,850 करोड़ रू. के खर्च से 10 हजार नए एफपीओ के गठन की स्कीम तथा किसानों के सशक्तिकरण के लिए नए कृषि सुधार कानून जैसे ठोस कदम खेती को समृद्धता देने वाले हैं, ये कृषि विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। 86 प्रतिशत छोटे-मझौले किसान इनके माध्यम से और मजबूत होंगे, जिससे देश की भी ताकत बढ़ेगी।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कोरोना के संकटकाल में भी केवीके के वैज्ञानिक, सूचना-संचार तकनीकों एवं कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों को उचित तकनीकों द्वारा लाभ पहुंचा रहे है, जो सराहनीय है। पशु धन एवं मछली पालन के विकास के लिए भी केवीके पूरे जज्बे के साथ कार्य कर रहे हैं तथा कृषि व सभी सम्बद्ध क्षेत्रों की सतत प्रगति व किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वर्तमान में 723 केवीके, आईसीएआर की इकाइयों, गैर सरकारी संस्थानों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे है, जिनसे किसानों को बहुत मदद मिल रही है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करते हुए अटारी, जबलपुर द्वारा नई परियोजना- 'आर्या' म.प्र.-छग के 12 केवीके में संचालित की जा रही है, जिसके तहत प्रसंस्करण, मशरूम व लाख उत्पादन, नर्सरी प्रबंधन आदि में 700 से ज्यादा युवाओं ने उद्यम स्थापित किए है।

अटारी, जबलपुर में 'फार्मर फर्स्ट' परियोजना तीन संस्थानों व चार विश्वविद्यालयों द्वारा चलाई जा रही है। इसके साथ-साथ 'मेरा गांव-मेरा गौरव' कार्यक्रम भी म.प्र.-छग के 5 विश्वविद्यालयों व 5 अन्य संस्थानों द्वारा संचालित किया जा रहा है। दलहनी फसलों के बीजों की उपलब्धता वृद्धि हेतु 15 जिलों में सीड हब कार्यक्रम का संचालन केवीके द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया तथा केवीके, गोविंद नगर, होशंगाबाद में सोयाबीन बीज हब भंडार गृह की आधारशिला रखी।

नामांतरण में सुधार के लिए रिकॉर्ड शुद्धिकरण सप्ताह मनाया जाएगा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अविवादित नामांतरण के लिए स्थापित नई व्यवस्था की जन-सामान्य को जानकारी देने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। भूमि संबंधी दस्तावेजों में त्रुटि सुधार के लिए अगस्त माह में एक सप्ताह का विशेष रिकॉर्ड शुद्धिकरण सप्ताह मनाया जाएगा। रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण के दौरान हुई त्रुटियों के सुधार के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान राजस्व, कृषि, विद्युत, सहकारिता, पशुपालन विभाग से संबंधित कार्यों में आने वाली समस्याओं के संबंध में किसान मंच के पदाधिकारियों से मंत्रालय में चर्चा किया।

बैठक में किसान प्रतिनिधियों के साथ कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के. के. सिंह, अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री जे.एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ट्रांसफार्मर बदले जाएं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जले ट्रांसफार्मर की जगह अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए सब स्टेशन स्तर पर शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए जाएं। प्रदेश में नकली दूध के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जाएगा।

सहकारी संस्थाओं की जाँच प्रशासनिक अधिकारी करेंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में मानक परीक्षा मशीनें लगाई जाएंगी। लहसुन, प्याज की सफाई में लगी महिलाओं को वे सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जो हम्मालों को मिलती हैं। सहकारी संस्थाओं की गंभीर शिकायतों की जांच अब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी।

किसान मंच से इन मुद्दों पर हुई बात

- रजिस्ट्री होते ही नामांत्रित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएं। फौती नामांतरत्रण समय-सीमा में हो। पटवारी ही कंप्यूटर रिकार्ड में दर्ज करें ।
- अविवादित बंटवारा आपसी सहमति के आधार पर तहसीलदार करें। विभाग द्वारा खसरा बी-1 में की गई त्रुटियों को विभाग द्वारा सुधारा जाए।
- खेतों के परंपरागत रास्तों का नक्शे में अंकन हो।
- आरआई एवं पटवारियों गृह तहसील में पदस्थ न हों।

योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और उनमें सुधार जरूरी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारों द्वारा विकास और जन-कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रभावशीलता का निरंतर मूल्यांकन और उनमें सुधार आवश्यक है, अन्यथा सरकारें वास्तविकता से अनजान बनी रहेंगी। विकास का प्रकाश जब तक गरीब तक नहीं पहुँचता तब तक विकास बेमानी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान नीति आयोग तथा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के बीच संस्थागत सहभागिता के लिए मिंटो हॉल में आयोजित एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष डॉ. सचिन चतुर्वेदी कार्यक्रम में उपस्थित थे। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" का नारा देते हुए गौरवशाली, वैभवशाली, सम्पन्न और समृद्ध भारत का स्वप्न देखा। उनका विश्वास था की देश की ताकत राज्यों में निहित है। इसके आधार पर सहयोगी संघवाद के विचार को क्रियान्वित करने के लिए नीति आयोग की अवधारणा अस्तित्व में आई। यह एक ऐसा मंच है जहाँ विषय-विशेषज्ञ विभिन्न विषयों, समस्याओं पर विचार करते हैं और उसके प्रभावी और व्यावहारिक समाधानों के क्रियान्वयन का

मार्ग प्रशस्त होता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाड़ली लक्ष्मी योजना, बालिकाओं को साइकिल प्रदाय के लिए संचालित योजना और सिटीजन चार्टर के समय-सीमा में पालन का उल्लेख करते हुए कहा कि योजनाओं की प्रभावशीलता के व्यवहारिक मूल्यांकन से योजनाओं को निरंतर बेहतर, जनोन्मुखी और विकासोन्मुखी बनाये रखने में मदद मिलती है। इन गतिविधियों में नीति आयोग के सहयोग और मार्गदर्शन से सुशासन संस्थान अधिक प्रभावी तरीके से कार्य करेगा। आज एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, यह दिन प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन-भागीदारी मॉडल से कोरोना नियंत्रण तथा टीकाकरण अभियान के संचालन और स्व-सहायता समूहों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार जनता को साथ लेकर योजनाओं का क्रियान्वियन कर रही है । कृषि में उत्पादन पर्याप्त है। अब हमें फूड प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ना है। कोरोना के परिणामस्वरूप योग और आयुर्वेद में बढ़ती जन-सामान्य की रूचि से प्रदेश में जड़ी-बूटियों की खेती और व्यापार के नये अवसर निर्मित हुए हैं। इस दिशा में भी राज्य सरकार कार्यरत है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर भारत के लिए आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश हमारा संकल्प है। आज हस्ताक्षरित एमओयू हमें नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई तकनीक के साथ काम कर रही केंद्र सरकार- नरेंद्र सिंह तोमर

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार देश के एक्सपर्ट्स, आईटी कंपनियों के साथ मिलकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई प्रौद्योगिकी के साथ कार्य कर रही हैं। यूआईडीएआई के साथ आधार एकीकरण, मोबाइल ऐप का शुभारंभ और सीएससी, केसीसी के साथ एकीकरण और राज्यों द्वारा बनाए गए भूमि रिकॉर्ड डाटाबेस के साथ एकीकरण के माध्यम से विभिन्न तकनीकी समाधान विकसित किए जा रहे हैं।

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि कार्य संबंधी व्यय हेतु प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना लागू की है। इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में 1.37 लाख करोड़ रूपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर यह बात कह रहे थे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति पीएम-किसान योजना, किसान मानधन योजना, कृषि अवसंरचना कोष और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निगरानी इकाई के रूप में कार्य करेगी।

इसके अलावा, पूसा परिसर स्थिति आयोजित एक कार्यक्रम में तोमर ने कहा कि पौधा प्राधिकरण के माध्यम से किसानों के अधिकारों का संरक्षण हो रहा है, जिसके लिए भारतीय संसद ने एक अनूठा मॉडल दिया है।

इससे किसान अपनी परंपरागत किस्मों के ऊपर और किसी अन्य किस्म के अपने ही पैदा किए हुए बीज का अधिकार प्राप्त कर सकता है. साथ ही, यह भी सुविधा है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से किसानों का शोषण न हो। किसान पहले की तरह स्वतंत्रता से खेती कर सकते हैं व पौधा प्रजनक भी अपने पूरे अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति' बुनियादी सुविधाओं व संशोधनों के साथ नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई है। जहां अन्य आईपीआर वाणिज्य मंत्रालय से सम्बद्ध हैं, वहीं पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कृषि मंत्रालय से संबद्ध है। केवल इसी आईपीआर के लिए फसलों को उगाया जाता है।

देश में 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद

49.15 लाख किसानों को 85,581 करोड़ रुपये का भुगतान

नई दिल्ली। वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के समापन के बाद अधिकांश गेहूं की खरीद वाले राज्यों से 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है और यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खरीद ने आरएमएस 2020-21 के पिछले उच्च स्तर 389.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के आंकडे को पार कर लिया है। पिछले साल की इसी समान अवधि में 387.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लगभग 49.15 लाख किसान मैजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके है और उन्हें 85,581.39 करोड रूपये का भुगतान किया जा चुका है।

वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 25.07.2021 तक 869.80 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है। (इसमें खरीफ फसल का 707.69 लाख मीटिक टन और रबी फसल का 162.11 लाख मीट्रिक टन धान शामिल है) जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 759.24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।

अंतिम किसान के खेत तक पानी पहुँचे - मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत निर्मित हो रही सभी परियोजनाओं में अंतिम किसान के खेत तक पानी पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए मंत्री तथा अधिकारी आवश्यक रूप से क्षेत्र भ्रमण करें। नर्मदा घाटी विकास के लिए किए जा रहे निवेश का शत-प्रतिशत लाभ अर्जित करना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पानी के प्रदाय से निश्चित रूप से किसानों का उत्पादन बढ़ेगा। किसानों में पानी और बिजली के शुल्क को जमा कराने के लिए दायित्व बोध विकसित किया जाए। यह जिम्मेदारी किसानों की समितियों को सौंपी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में आयोजित नर्मदा नियंत्रण मंडल की 70वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।

लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास एवं अपर मुख्य सचिव श्री आई.सी.पी. केसरी बैठक में उपस्थित थे।

भारत खाद्यान्न निर्यातक देश बन के उभरा : सुश्री शोभा करंदलाजे

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 के "टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खाद्य प्रणालियों में बदलाव : बढ़ती चुनौती" पर पूर्व-शिखर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन ने हमें अपनी खाद्य प्रणालियों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रणालियों में बदलने और उसके लिए राष्ट्रीय नीति की रुपरेखा तय करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। सम्मेलन के दौरान उन्होंने भारत द्वारा कृषि-खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ व्यवस्था में बदलने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे जानकारी दी। इसके तहत किसानों को आय सहायता प्रदान करना, ग्रामीण आय में सुधार करना, साथ ही देश में अल्प पोषण और कुपोषण जैसी चुनौतियों का समाधान करने जैसे उपाय शामिल है।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य देशों को वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष' के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। मंत्री ने सम्मेलन में भरोसा दिलाया कि भारत टिकाऊ विकास लक्ष्यों 2030 को हासिल करने के लिए अपनी कृषि-खाद्य प्रणालियों में सतत बदलाव लाने और उसे टिकाऊ प्रणाली बनाने के प्रयास लगातार करता रहेगा।

झींगा उत्पादन से युवाओं को जोड़ रोजगार के नए अवसर बनाए : मंत्री श्री सिलावट

भोपाल। जल-संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिये की प्रदेश में झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य-योजना बनाई जाये और इससे युवाओं को जोड़ा जाये, जिससे रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा की मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक मछुआ परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करना है। इसके लिए लगातार नवाचार किया जाये और अच्छे मछली बीज उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाये, जिससे मछली की गुणवत्ता में सुधार हो और मछली उत्पादन में मार्केट की माँग और बाजार मूल्य के आधार पर मछली बीज तैयार किया जाये। मत्स्य महासंघ के जलाशयों में उच्च गुणवत्ता का बीज डाला जाये। मछली के फीडिंग के लिए अवश्य सभी जरूरी व्यवस्थाएँ भी की जायें।

अपर मुख्य सचिव श्री अश्विनी कुमार ने बताया कि प्रदेश में 4 लाख 30 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जलाशय हैं, जिनमें मछली उत्पादन का काम किया जा रहा है। इसमें मत्स्य महासंघ के पास 2 लाख 28 हजार हेक्टेयर से अधिक के जलाशय हैं। इसमें उत्पादन बढ़ाये जाने की अधिक संभावना है। इसके साथ मछली की गुणवत्ता के लिए भी अच्छे बीज उत्पादन के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में झींगा उत्पादन को बढ़ाने के लिये भी बेसिन नदी में लगातार प्रयास जारी हैं। इस वर्ष 50 टन से अधिक झींगा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे पूरा किया जायेगा। मछुआरों को विशेष प्रशिक्षण के लिए झींगा उत्पादन केंद्रों पर भेजे जाने की कार्य-योजना भी बनाई जा रही है।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए विशेष मुहिम शुरू की जाये और सभी पात्र लोगों के कार्ड बनवाये जायें। शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिये और इसके लिए अधिकारी मछुआ कल्याण महासंघ के लोगों से निरंतर चर्चा करें और विभाग की योजना के संबंध में बतायें। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट का पूरा उपयोग किया जाये।

दाल आयातकों को स्टॉक सीमा से छूट दी गई

नई दिल्ली । दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के बाद केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे किसानों को काफी मदद मिलेगी। कीमतों में नरमी आने और राज्य सरकारों तथा विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मिल मालिकों एवं थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा में ढील दी है तथा आयातकों को इससे छूट दी गई है । हालांकि इन संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के वेब पोर्टल पर अपने स्टॉक की घोषणा करनी होगी । स्टॉक सीमा केवल तुअर (अरहर), उड़द, चना और मसूर दाल पर लागू होगी।

संशोधित आदेश में प्रावधान किया गया है कि स्टॉक सीमा केवल अरहर, मसूर, उड़द और चने पर 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी । यह निर्णय लिया गया है कि दालों के आयातकों को स्टॉक सीमा से छूट दी जाएगी और वे उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in) पर दालों के स्टॉक की घोषणा करना जारी रखेंगे ।

थोक विक्रेताओं के लिए, स्टॉक सीमा 500 मीट्रिक टन होगी (बशर्ते एक किस्म की 200 मीट्रिक टन से अधिक का स्टॉक नहीं होना चाहिए; खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक की सीमा 5 मीट्रिक टन होगी और मिल मालिकों के लिए स्टॉक की सीमा पिछले 6 महीने का उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो) खरीफ मौसम में अरहर और उड़द की बुवाई के इस महत्वपूर्ण समय पर किसानों को आश्वासन देने के मामले में मिल मालिकों के लिए इस छूट का डाउन-स्ट्रीमिंग प्रभाव होगा।

मिट्टी की नमी का सूचक यंत्र

इंदौर । मिट्टी की नमी का सूचक यंत्र – किसानों की सुविधा के लिए नित नए यंत्र विकसित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आईसीएआर-एसबीआई,कोयंबटूर द्वारा विकसित एवं सोर्स टेक साल्यूशंस कम्पनी बेंगलुरु द्वारा निर्मित मिट्टी की नमी जांचने का यह ऐसा सूचक यंत्र है , जिससे खेत की नमी को आसानी से जांचा जा सकता है और यह पता लगाया जा सकता है, कि फसल को सिंचाई की जरूरत है या नहीं। यह यंत्र पानी की बचत में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

सोर्स टेक साल्यूशंस कम्पनी के श्री विनय कृष्णा ने कृषक जगत को बताया कि इस यंत्र से मिट्टी की नमी को आसानी से जांचा जा सकता है। इसमें दो रॉड लगी हुई है , जिन्हें ज़मीन में गाड़ते ही मिट्टी की नमी का पता इस यंत्र में लगे चार एलईडी से चल जाता है। इसमें नीला रंग पर्याप्त नमी का संकेत देकर सिंचाई नहीं करने का संकेत देता है , जबकि हरा रंग तुरंत सिंचाई नहीं करने का संकेत देता है। नारंगी रंग कम नमी की ओर इशारा कर सिंचाई करने का संकेत देता है , वहीं लाल रंग तुरंत सिंचाई करने की ज़रूरत को बताता है। इस यंत्र की अधिकतम कीमत 1650 रुपए है। श्री कृष्णा ने कहा कि इस मृदा नमी संकेतक को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जल संरक्षण के लिए नई तकनीक के सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला पुरस्कार मिला है ।

मण्डी बोर्ड की जानकारी अब पोर्टल पर होगी

भोपाल । मण्डी बोर्ड के निर्माण कार्यों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित होगी – मण्डी बोर्ड के तहत होने वाले समस्त निर्माण कार्यों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड की आयुक्त-सह-प्रबंध संचालक सुश्री प्रियंका दास ने मण्डी बोर्ड के कार्यपालन यंत्रियों को यह निर्देश बैठक में दिये । सुश्री प्रियंका दास ने बैठक में निर्देशित किया कि पोर्टल पर निर्माण कार्य से संबंधित समस्त जानकारियाँ अपलोड की जायें, जिसमें स्थान, क्रियान्वयन एजेंसी का नाम, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, कार्य प्रारंभ होने से लेकर कार्य समाप्ति के दिनांक का भी उल्लेख ऑनलाइन किया जाये । बैठक में मण्डी बोर्ड भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, खरगोन, उज्जैन, मंदसौर, ग्वालियर, मुरैना, सागर, जबलपुर, सिवनी एवं रीवा के कार्यपालन यंत्री मौजूद थे ।

यूरिया-डी.ए.पी. की लम्बित मांग शीघ्र पूरी करें

भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर अनुरोध किया कि केन्द्र में यूरिया और डी.ए.पी. की लम्बित मांग को शीघ्रातिशीघ्र जारी किया जाय जिससे किसानों को बुआई में किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न न होने पाये । उन्होने फार्मा क्षेत्र में विस्तार के लिए प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया।

श्री चौहान ने बताया कि 1276 करोड़ रुपये की लागत के बल्क ड्रग पार्क और 193 करोड़ रुपये की लागत के मेडिकल डिवासेस पार्क के प्रस्ताव केन्द्र में स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा मूल्यांकन के लिए नियुक्त आई.एफ.सी.आई.ने प्रस्तावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रस्तावित पार्क के लिए राजधानी भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर दूर मोहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र में 2400 एकड़ भूमि भी चिन्हित कर ली गई है । इसके अलावा लगभग 1500 एकड़ भूमि में उद्योगों की आवश्यकतानुसार अधोसंरचना विकसित की जा चुकी है। उद्योगों के लिए 4.50 रुपये प्रति यूनिट पर प्रचुर मात्रा में बिजली भी उपलब्ध है । केन्द्रीय मंत्री श्री मांडविया ने मुख्यमंत्री को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया ।

वैज्ञानिकों ने विकसित की नई पॉलीहाउस तकनीक

किसानों को अत्यधिक या अपर्याप्त ठंड, गर्मी, बारिश, हवा, और अपर्याप्त वाष्पोत्सर्जन एवं कीट रोगों के चलते फसल का काफी नुकसान उठाना पड़ता है | इसके आलवा खुले वातावरण में किसान सभी तरह की फसलों की खेती नहीं कर सकते हैं | इससे बचाव के लिए पॉलीहाउस में किसी भी मौसम में बाजार की मांग के अनुसार खेती की जा सकती हैं | जिससे फसलों के अच्छे दाम मिलते हैं और अधिक मुनाफा होता है | परन्तु पारंपरिक पॉलीहाउस में कई कमियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए नए तरह के पालीहाउस तकनीक को विकसित किया गया है |वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएमईआरआई), दुर्गापुर के निदेशक डॉ. (प्रो.) हरीश हिरानी ने पंजाब के लुधियाना में "नेचुरली वेंटिलेटेड पॉलीहाउस फैसिलिटी" का उद्घाटन किया और "रिट्रैक्टेबल रूफ पॉलीहाउस" की आधारशिला रखी।

अभी के पारंपरिक पालीहाउस में क्या है कमियाँ

प्रोफेसर हिरानी ने प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को अत्यधिक या अपर्याप्त ठंड, गर्मी, बारिश, हवा, और अपर्याप्त वाष्पोत्सर्जन से जुड़े अन्य कारकों जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और साथ ही भारत में कीटों के कारण भी वर्तमान में लगभग 15 प्रतिशत फसल का नुकसान होता है तथा यह नुकसान बढ़ सकता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन कीटों के खिलाफ पौधों की रक्षा प्रणाली को कम करता है। पारंपरिक पॉलीहाउस से कुछ हद तक इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। पारंपरिक पॉलीहाउस में मौसम की विसंगतियों और कीटों के प्रभाव को कम करने के लिए एक स्थिर छत होती है। छत को ढंकने के अब भी नुकसान हैं जो कभी-कभी अत्यधिक गर्मी और अपर्याप्त प्रकाश का कारण बनते हैं। इसके अलावा, वे कार्बन डाईऑक्साइड, वाष्पोत्सर्जन और जल तनाव के अपर्याप्त स्तर के लिहाज से भी संदेवनशील होते हैं। खुले क्षेत्र की स्थितियों और पारंपरिक पॉलीहाउस स्थितियों का संयोजन भविष्य में जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिहाज से एक ज्यादा बेहतर तरीका है।

क्या है रिट्रैक्टेबल रूफ पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी

केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमईआरआई) एक्सटेंशन सेंटर लुधियाना में एक "रिट्रैक्टेबल रूफ पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी" स्थापित कर रहा है। हर मौसम में काम करने के लिहाज से उपयुक्त इस प्रतिष्ठान में ऑटोमैटिक रिट्रैक्टेबल रूफ (स्वचालित रूप से खुलने-बंद होने वाली छत) होगी जो पीएलसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कंडीशनल डेटाबेस से मौसम की स्थिति और फसल की जरूरतों के आधार पर संचालित होगी। इस प्रौद्योगिकी से किसानों को मौसमी और गैर-मौसम वाली दोनों ही तरह की फसलों की खेती करने में मदद मिलेगी। यह पारंपरिक खुले मैदानी सुरंगों और प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउस की तुलना में इष्टतम इनडोर सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों का निर्माण करके उच्च उपज, मजबूत और उच्च शेल्फ-लाइफ उपज प्राप्त कर सकता है, और साथ ही यह जैविक खेती के लिए व्यवहार्य प्रौद्योगिकी भी है। इस प्रौद्योगिकी के विकास में लगे अनुसंधान दल का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री जगदीश माणिकराव ने बताया कि रिट्रैक्टेबल रूफ का उपयोग सूर्य के प्रकाश की मात्रा, गुणवत्ता एवं अवधि, जल तनाव, आर्द्रता, कार्बन डाई-ऑक्साइड और फसल एवं मिट्टी के तापमान के स्तर को बदलने के लिए किया जाएगा। यह मौसम की जरूरतों और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) पर आधारित होगा तथा सक्षम किसान अनुकूल यूजर इंटरफेस प्रदान करेगा।

गोपाल रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन

कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसानों को विभिन्न योजना के तहत पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार राज्यों में विभन्न स्तरों एवं राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुपालक एवं डेयरी किसानों को यह पुरस्कार देने के लिए "राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना" चलाई जा रही है। जिसके तहत देश में डेयरी किसानों को नवाचार करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है।इससे किसानों का पशुपालन के प्रति उत्साह बना रहता है। इस वर्ष भी किसानों को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृत्रिम गर्भधान तकनीशियनों को 100 प्रतिशत एआई कवरेज लेने तथा सहकारी एवं दुग्ध उत्पादक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। इस योजना से जुडी सभी प्रकार की

तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार- योजना के तहत पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में तीन श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। यह श्रेणियां इस प्रकार है:- सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान जो देसी गायों का पालन करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (AI), डेयरी सहकारिता/ दुग्ध उत्पादक कंपनी/ डेयरी किसान उत्पादक संगठन।

गोपाल रत्न पुरस्कार हेतु पात्रता- इस योजना का लाभ राज्य के डेयरी किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भधान तकनीशियन और सहकारी एवं दुग्ध उत्पादक कंपनियों के द्वारा प्रमाणित 50 नस्लों के गाय अथवा 17 देशी प्रमाणित नस्लों में से किसी एक का पालन कर डेयरी करने वाले किसान इसके लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार सर्वश्रेठ कृत्रिम गर्भधान तकनीशियन पुरस्कार के लिए 90 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए राज्य पशुधन विकास बोर्ड, दुग्ध फेडरेशन, गैर सरकारी संगठन एवं निजी क्षेत्र के कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन पात्र होंगे। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी एवं कंपनी अधिनियम के तहत ग्राम स्तर पर स्थापित कम से कम 50 किसान सदस्यों एवं प्रतिदिन 100 लीटर दूध का उत्पादन करने वाली सहकारी समिति, एमपीसी, एफपीओ एवं दुग्ध उत्पादक कम्पनी पात्र होंगे।

कितना पुरस्कार दिया जायेगा ? देश के पशुपालकों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत "गोपाल रत्न पुरस्कार" दिया जा रहा है। इसके तहत राज्य के पशुपालकों को तीन श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार में 5 लाख रूपये, दिव्तीय पुरस्कार में 3 लाख रूपये, तृतीये पुरस्कार में 2 लाख रूपये दिये जाएंगे।

गोपाल रत्न पुरस्कार योजना के तहत कब आवेदन करें ? योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। देश के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 15 सितम्बर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहें हैं। पात्र व्यक्ति अभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत चयनित पशुपालकों को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर 26 नवम्बर को समारोह आयोजित कर पुरस्कार प्रदान करेगी।

गोपाल रत्न योजना के तहत आवेदन कहाँ करें - राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक देशव्यापी योजना है, योजना के तहत देश के सभी राज्यों के व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं। किसी भी राज्य के इच्छुक कृत्रिम गर्भधान तकनीशियन और सहकारी एवं दुग्ध उत्पादक कम्पनियां www.dahd.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 011-23383479 पर कॉल कर सकते हैं।

कृषकों से पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित

विदिशा। आत्मा परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में वैज्ञानिक पद्धति से कृषि के लिए जिले के किसान भाईयों से पुरस्कार हेतु आवेदन 31 अगस्त तक कृषि विभाग द्वारा आमंत्रित किए गए है। आत्मा परियोजना के संचालक ने बताया कि विकास खण्ड स्तर पर सर्वोत्तम कुल पांच जो कृषि, पशुपालन, उद्धानिकी, रेशम विभाग अंतर्गत एक-एक श्रेष्ठत कृषक को पुरस्का र प्रदाय किया जाएगा। इस प्रकार जिले के सभी सातों विकासखण्डों के लिए पृथक-पृथक प्रत्येक पुरस्कार प्रदाय किए जाएंगे। पृथक-पृथक प्रत्येक सेक्टर में विकास खण्ड स्तर पर चयनित कृषक को दस हजार रूपए तथा जिला स्तर पर सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार में 25 हजार रूपए की राशि प्रदाय की जाएगी। प्रत्येक समूह में पुरस्कार राशि 20 हजार रूपए प्रदाय की जाएगी। इच्छुक कृषक आवेदन विकास खण्ड के बीटीएम, एटीएम या कृषि कार्यालय से प्राप्त कर अंतिम तिथि 31 अगस्त तक जमा कर सकते है।

मत्स्य कृषक और मछुआरों के लिए चलाई जा रही हैं अनेक योजनाएं

भोपाल। मत्स्य पालन से जुड़े कृषकों तथा मत्स्य पालन करने के इच्छुक जिले के व्यक्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 मे भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग में आवेदन आमंत्रित किये गये है।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि इच्छुक मत्स्य पालक/व्यक्ति मत्स्य विभाग में संपर्क कर विभिन्न योजनाएं जैसे मत्स्य बीज उत्पादन हेतु हैचरी निर्माण, संवर्धन पोंड निर्माण, नवीन तालाब निर्माण, मत्स्य पालन हेतु इनपुट्स की व्यवस्था, जलाशय में मत्स्य बीज फिंगरलिंग संचयन, रंगीन मछलियों की रियरिंग एवं ब्रीडिंग ईकाई स्थापना, मत्स्य मार्केटिंग हेतु क्योस्क, मोटरसाईकिल विथ आईस बाक्स, साईकिल विथ आईस बाक्स, रेफ्रीजरेटर व्हीकल, इंसुलेटेड व्हीकल, जलाशय में केज/पेज स्थापना, फिश फीड मिल प्लांट, आईस प्लांट, बायोफ्लोक प्लांट, आर.ए.एस. यूनिट, इत्यादि योजनाओं का लाभ ले सकते है। उन्होंने बताया कि इन योजना में सम्मिलित गतिविधियों का लाभ लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/मत्स्य समिति/समूह कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग में 30 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते है।

कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधन बोर्ड में धनश्याम भाई अमीन नियुक्त

पुणे। श्री धनश्याम भाई अमीन को कॉसमॉस को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे का प्रबंधन में बीओएम नियुक्तु किया गया है। श्री अमीन भारतीय सहकारी बैंक नई दिल्लीी के अध्यक्ष और गुजरात राज्यं सहकारी संघ अहमदाबाद के भी अध्यधक्ष है। श्री अमीन एक प्रमुख अधिवक्ताअ के साथ ही एक प्रतिष्ठित को-आपरेटर भी है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों में निर्धारित है, यह प्रत्येक शहरी सहकारी समिति के लिए अनिवार्य है कि बैंक निदेशक मंडल के अलावा प्रबंधन बोर्ड का गठन करेगा, ताकि पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंकिग से सबंधित गतिविधियों के विकास पर ध्या,न क्रेन्द्रित किया जा सके। यह भी निर्धारित किया गया है कि शहरी सहकारिता बैंकों को पेशेवर कौशल, विशेषज्ञता वाले व्यक्ति को नियुक्तत करना होगा। विशेष तौर पर लेखा, कृषि, ग्रामीण में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव अर्थव्यवस्था, बैंकिग, सहयोग, अर्थशास्त्र, वित्त , कानून या कोई अन्य बैंक के बीओएम पद पर एक सदस्य के रूप मे बैंक के लिए विशेष उपयोगी होंगे। को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की महाराष्ट्र, गुजरात में शाखाएं है। तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, दिल्ली आदि को दूसरा सबसे बड़ा माना जाता है, 1500 शहरी बैकों में से एक बैंक। भारत में कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने तीन विशेषज्ञ सदस्यों को नियुक्त किया है। इसका वर्तमान बोर्ड यानि एक अध्यक्ष और अन्य, दो सदस्य जिनके पास अनुभव है बैकिंग और एकाउंटेसी में।

आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए की गई नियुक्ति

निदेशक मंडल के ऊपर तीन विशेषज्ञ कॉसमॉस सहकारी बैंक के बीओएम पद पर सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है लिमिटेड इन तीन विशेषज्ञों में से श्री धनश्याम भाई अमीन को नियुक्त किया गया है गुजरात से कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बीओएम के सदस्य के रूप में कानूनी क्षेत्र , सहकारी क्षेत्र और उनके लंबे और विशाल अनुभव को देखते हुए बैंकिंग क्षेत्र। इसके अलावा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और एक डॉक्टर महाराष्ट्र को अन्य दो विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में चुना और नियुक्त किया गया है, कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बीओएम पर।

इस प्रकार ये तीन विशेषज्ञ कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बीओएम पर नियुक्त किए गए है और आरबीआई ने बीओएम के लिए उनकी नियुक्तियों के लिए इसके अनुमोदन की मुहर लगाई। अमीन के पेशेवर कौशल से कॉसमॉस बैंक को अत्यनधिक लाभ होगा, सहकारी क्षेत्र में विशेषज्ञता और विशाल अनुभव और एक्सवपोजर से यह गुजरात के लिए गर्व की बात है कि श्री अमीन को बीओएम में नियुक्त किया गया है।

गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने से मुझे ताकत....

प्रधानमंत्री ने की मध्यप्रदेश की प्रशंसा

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को मदद पहुँचाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। प्रदेश में किसानों ने रिकार्ड उत्पादन किया और राज्य शासन ने एमएसपी पर रिकार्ड मात्रा में खरीद की व्यवस्था भी की। मध्यप्रदेश में गेहूँ की खरीद के लिए देश में सबसे अधिक खरीद केन्द्र बनाए गए। राज्य सरकार ने 17 लाख से अधिक किसानों से गेहूँ खरीदा और उनके खातों में 25 हजार करोड़ रूपए सीधे पहुँचाये।

डबल इंजन सरकार लाभकारी

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि केन्द्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार और सँवार देती है। इससे योजनाओं की ताकत बढ़ती है। मध्यप्रदेश में स्किल डेव्हलपमेन्ट, स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण, डिजिटल इन्फ्रा-स्ट्रक्चर, रेल तथा रोड कनेक्टिविटी आदि क्षेत्रों के कार्यों में अभूतपूर्व गतिशीलता है।

कोरोना 100 साल में आयी सबसे बड़ी आपदा

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कोरोना 100 साल में आयी सबसे बड़ी आपदा है। हमारे देश की जनसंख्या अधिक होने के कारण हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ा। हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना तैयार करने के साथ करोड़ों लोगों को राशन पहुँचाने, उनके रोजगार की व्यवस्था करने जैसी चुनौतियों का भी सामना करना था। इन परिस्थितियों में सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब को दी गई। 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को नि:शुल्क राशन पहुँचाने के साथ 08 करोड़ लोगों को गैस और 20 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन-धन खातों में 30 हजार करोड़ रूपए ट्रांसफर किए गए। श्रमिकों और किसानों के बैंक खातों में भी हजारों करोड़ रूपए सीधे जमा कराए गए। इसी क्रम में दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों के लिए "वन नेशन-वन राशन कार्ड" की व्यवस्था की जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना में आसान बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

त्यौहारों पर लें हस्तशिल्प उत्पाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 7 अगस्त को ही 1905 में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। इस दिवस पर हाथकरघा को समर्पित किया गया है। हस्तशिल्प, हाथकरघा और कपड़े की कारीगरी को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने त्यौहारों में हस्तशिल्प का कोई न कोई उत्पाद लेकर लोकल उत्पाद को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई।

कोरोना के प्रति सतर्कता आवश्यक

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के प्रति सतर्कता आवश्यक है। आने वाले दिनों में उत्सवों के बीच कोरोना की प्रति लापरवाही उचित नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। मास्क, टीकाकरण और दो गज की दूरी का पालन आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमें स्वस्थ और समृद्ध भारत का संकल्प लेना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश की 25 हजार से अधिक दुकानों पर एकत्र हुए प्रदेशवासियों का आभार माना।

विकास गरीब तक नहीं पहुँचे तो वह बेमानी है – मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की ओर से स्वागत करते हुए कहाकि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश का दसों दिशाओं में विकास हुआ है। उनका वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और सम्पन्न भारत बनाने का संकल्प है। विकास का प्रकाश जब तक गरीब तक नहीं पहुँचे, उसकी जिन्दगी में जब तक बदलाव नहीं आए, तब तक विकास बेमानी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। यह सुनिश्चित किया कि एक दिन की मजदूरी में पूरे महीने का राशन आए और शेष दिन की मजदूरी गरीब को अपने जीवन स्तर में सुधार के लिये उपलब्ध हो। प्रदेश के 1 करोड़ 15 लाख परिवारों के 4 करोड़ 90 लाख लोगों को नाम मात्र की दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 7 हजार 441 करोड़ रूपए का अनुदान देने के परिणामस्वरूप संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सहयोग और उनकी किसानों के प्रति संवदेनशीलता के परिणामस्वरूप ही इस वर्ष 1918 रूपए क्विंटल गेहूँ खरीदा गया।

प्रदेश में 2024 तक कोई भी गरीब पक्की छत के बिना नहीं रहेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोरोना की पहली लहर में गरीबों की मदद की व्यवस्था की। दूसरी लहर में नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का वर्ष 2016 से अब तक प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए 26 लाख 27 हजार 899 परिवारों को 32 हजार 204 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध करवाने पर आभार माना। शहरी क्षेत्र में 07 लाख 37 हजार 616 मकानों के लिए 32 हजार 156 करोड़ रूपए गरीबों को उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि वर्ष 2024 तक प्रदेश का कोई भी गरीब पक्की छत के बिना नहीं रहेगा।

भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी - धन्यवाद मोदी जी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी - धन्यवाद मोदी जी के वाक्य के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार मानते हुए कहा कि प्रदेश में ढाई करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। अब 5 लाख रूपए तक का इलाज सरकारी के साथ चिन्हित अनुबंधित अस्पतालों में नि:शुल्क होगा। कोरोना के संकट में मनरेगा की मजदूरी के रूप में 13 हजार 163 कार्यों की 8 हजार 844 करोड़ रूपए की मजदूरी सीधे श्रमिकों के खातों में डाली गई। फुटपाथ पर काम करने वालों और हाथ-ठेला वाले 3 लाख 32 हजार लोगों को 332 करोड़ की राशि काम-धंधे पुन: आरंभ करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उपलब्ध कराई गई। ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर हम धन्य और गौरवान्वित है।

अन्य राज्यों के मंत्री भी कार्यक्रम में हुए सम्मिलित

सात राज्यों के मंत्री और विधायक भी कार्यक्रम में अलग-अलग जिलों से सम्मिलित हुए। उत्तराखंड के खाद्य मंत्री श्री सुबोध उनियाल भोपाल से, असम के मंत्री श्री रंजीत कुमार दास होशंगाबाद से, त्रिपुरा के मंत्री श्री प्राणजीत सिंघा रॉय सीहोर से, हिमाचल प्रदेश के मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग रायसेन से और गोवा के मंत्री श्री गोविंद गौड़े इंदौर से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के विधायक श्री जिगुन नाम चुन रायसेन से और हरियाणा के विधायक श्री सत्य प्रकाश जरावता ने देवास से कार्यक्रम में शिरकत की।

प्रदेशवासी वर्चुअली जुड़े कार्यक्रम से

कार्यक्रम को खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह तथा सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपस्थित लोगों ने वुर्चअली सहभागिता की। कार्यक्रम से टी.वी. चैनलों, वेबकास्ट और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से भी प्रदेशवासी जुड़े।

ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द के खरीदी लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध

मुख्यमंत्री की केन्द्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात

भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली मे केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के उपार्जन के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि राज्य में पंजीकृत किसानों द्वारा मूंग की फसल को अधिकाधिक केन्द्र द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाय, जिससे किसानों को उनकी पैदावार का सही मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए 5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त का लक्ष्य एवं उड़द के लिए 0.61 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया।

श्री चौहान ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग का 34020 मीट्रिक टन का अधिकतम उपार्जन करने का लक्ष्य और मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना में मूंग फसल का एक लाख मीट्रिक टन उपार्जन करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार मूंग का कुल 1.34 लाख मीट्रिक टन उपार्जन लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं। श्री चौहान ने बताया कि वर्ष 2020-21 में प्रदेष का कुल दलहन उत्पादन 64.94 लाख मीट्रिक टन है,जबकि कुल उपार्जन का लक्ष्य 17.23 लाख मीट्रिक होता है। अतः 17.23 लाख मीट्रिक टन उपार्जन किया जाना शेष हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में लगभग 3.2 लाख किसानों द्वारा 12 लाख मीट्रिक टन मूंग उपार्जन के लिए पंजीयन हुआ है। प्रदेश को अब तक 1.34 लाख मीट्रिक टन मूंग उपार्जन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जो अत्यन्त कम है। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

"पर ड्राप, मोर क्रॉप" योजना के लिए मार्गदर्शी निर्देश जारी

इंदौर । आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक 'पर ड्राप, मोर क्रॉप' योजना के लिए किसानों के हित में अधीनस्थ उप/सहायक संचालक को हाल ही में जारी पत्र में 5 मार्गदर्शी बिंदुओं में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए है।

इस पत्र में कहा गया है कि किसान के खेत पर संयंत्र स्थापित होने के बाद निर्माता कंपनी द्वारा दिए गए बिल पर ही कृषक से प्रदाय की पावती प्राप्त करें जिसमें उसका नाम, हस्ताक्षर और मोबाईल नंबर स्पष्ट अंकित हो। कृषक संतुष्टि प्रमाण पत्र में भी निर्माता कंपनी द्वारा दी गई सामग्री का उल्लेख किसान की पूरी जानकारी के साथ हों।

पंचनामा प्रमाणपत्र को गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने तैयार करें, जिसमें सभी के नाम, हस्ताक्षर और मोबाईल नंबर दर्ज हो। अन्य निर्देश में कहा गया है कि कृषक को mpfsts पोर्टल पर जारी कार्य आदेश में ही यह शामिल किया जाए कि किसान संयंत्र स्थापित होने के बाद किसी अन्य को नहीं बेचेगा। भौतिक सत्यापन समिति, सामग्री का परीक्षण कर निर्माता कंपनी द्वारा किसान को प्रदाय देयक पावती पर हस्ताक्षर करेगी। यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

उल्लेखनीय है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा mpfsts पोर्टल पर किसानों को कृषि यंत्र, सिंचाई उपकरण, उद्यानिकी उपकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन/आवेदन की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से सरलता से समझाया गया है एवं किसानों की जिज्ञासाओं और समस्याओं का भी समाधान किया जाता है।

अन्य राज्यों के खाद्य मंत्रियों ने समझी प्रदेश में गेहूँ उपार्जन, भंडारण, वितरण की कार्य प्रणाली

प्रमुख सचिव खाद्य श्री किदवई ने दिया प्रजेन्टेशन

भोपाल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अवसर पर आयोजित अन्न उत्सव में पधारे 7 राज्यों के खाद्य मंत्रियों एवं विधायकों ने मध्यप्रदेश में गेंहूँ के बम्पर उपार्जन के साथ भंडारण एवं वितरण व्यवस्था को देखा और समझा। कार्यक्रम में उत्तराखंड के खाद्य मंत्री श्री सुबोध उनियाल, अरूणाचल प्रदेश के मंत्री श्री कमलुंग मोशांग, असम के मंत्री श्री रंजीत कुमार दास, त्रिपुरा के कृषि मंत्री श्री प्रंजीत राय, हिमाचल प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री राजेन्द्र गर्ग एवं सचिव श्री पॉल वाशु एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज़ अहमद किदवई ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी। इस अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत किया।

2020-21 गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश रहा टॉप पर

संचालक खाद्य एवं प्रबंध संचालक वेयर हाऊसिंग लॉजिस्टिक कार्पोरेशन श्री तरूण पिथोड़े ने बताया कि वर्ष 2020-21 में मध्यप्रदेश में 129.42 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया था, देश में सर्वाधिक था। उन्होंने कहा कि यह और भी ज्यादा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस अवधि में कोरोना संक्रमण अपने तीव्रतम स्वरूप में था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में इस वर्ष उपार्जन 128.16 लाख मेट्रिक टन के साथ पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर रहा। उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्षो के उपार्जन का आंकलन करें तो मध्यप्रदेश ने लगभग डबल उपार्जन के नजदीक पहुँचा है। इस वर्ष सर्वाधिक 24 लाख 72 हजार किसानों ने उपार्जन के लिए अपना पंजीयन करवाया, जिसमें से 17 लाख 16 हजार किसानों से उनका अनाज उपार्जित किया गया।

उपार्जन की दृष्टि से प्रदेश में धान

प्रबंध संचालक श्री अभिजीत अग्रवाल ने बताया कि इसी प्रकार धान उपार्जन के क्षेत्र में प्रदेश में विगत चार वर्षो की तुलना में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक 37 लाख मेट्रिक टन का उपार्जन किया गया। किसानों से 1868 रूपये एमएसपी पर धान क्रय की गई। एमएसपी विगत चार वर्षो की तुलना में सर्वाधिक सुनिश्चित की गई। वर्ष 17-18 से एमएसपी प्रतिवर्ष रूपये प्रति क्विंटल 1550,1750,1815 एवं 1868 क्रमशः वृद्धि होती गई। श्री अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष गेहूँ उपार्जन के लिए लगभग 16 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। इसमें 25 करोड़ बारदानों में 95 ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से 8000 ट्रकों का उपयोग कर 2000 गोदामों में खाद्यान्न सुरक्षित रखवाया गया।

उपार्जन की प्रक्रिया स्टेप टू स्टेप

प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री अभिजीत अग्रवाल ने गेहूँ उपार्जन की प्रक्रिया के बारे में बताया कि किसानों का उपार्जन के लिए पंजीयन किया जाता है, उसके बाद उन्हें एसएमएस के माध्यम से उनके द्वारा पंजीकृत मात्रा में खाद्यान्न निर्धारित तिथि को विक्रय के लिए आमंत्रित किया जाता है। गेहूँ उपार्जन के पश्चात परिवहन किया जाकर गोदाम में सुरक्षित रखा जाता है। खाद्यान्न की क्वलिटी चेक के बाद किसानों के खाते में ऑन लाइन भुगतान किया जाता है।

उद्यानिकी विभाग मसाला फसलों के बीज खरीदेगा : श्री कुशवाह

भोपाल। फल, सब्जी और मसाला फसलों की उन्नत किस्म के बीजों को केरल, असम सहित अन्य राज्यों से भी उद्यानिकी विभाग खरीदेगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने 17 जिलों के सब्जी, फल मसाला फसलों के उत्पादक किसानों से वर्चुअली संवाद करने के बाद अधिकारियों को यह निर्देश दिये। राज्य मंत्री निवास स्थित कार्यालय से प्रदेश के सब्जी, फल और मसाला उत्पादक किसानों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। श्री कुशवाह ने कहा कि प्रदेश के 52 जिलों में जिन जिलों को मसाला खेती, सब्जी खेती और फल की खेती के लिये चुना गया है। उन जिलों में इन फसलों के उत्पादन से जुड़े किसानों से सीधी बातचीत कर किसानों की जमीनी जरूरतों को समझने का प्रयास है। वर्चुअली कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री कुशवाह के साथ आयुक्त उद्यानिकी श्री एम. के. अग्रवाल और सभी 17 जिलों के उद्यानिकी जिला कार्यालयों उद्यानिकी अधिकारियों के साथ किसान बंधु मौजूद थे।

इस पर राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि किसानों को जिस प्रजाति और किस्म का बीज चाहिए है। वह उपलब्ध कराया जायेगा। राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने एक जिला-एक उत्पाद में मसाला फसलों में अदरक के लिये चयनित बडवानी, टीकमगढ, निवाडी, लहसुन के लिये मंदसौर और रतलाम, हरी मिर्च के लिये खरगोन, हल्दी के लिये रीवा एवं शहडोल और धनिया के लिये गुना और नीमच के किसानों से संवाद किया। फल में सीताफल के लिये अलीराजपुर, धार, सिवनी, आम के लिये अनूपपुर, बैतूल, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया, अमरूद के लिये भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर, श्योपुर, केला के लिये बुरहानपुर, संतरा के लिये आगर-मालवा, राजगढ और आंवला के लिये पन्ना जिले के किसानों से संवाद किया। सब्जियों में प्याज के लिये एक फसल-एक उत्पाद में चयनित हरदा, खण्डवा, शाजापुर, विदिशा और उज्जैन जिलों के किसानों से चर्चा की।

सबके लाभ, सबके कल्याण की सोच ही सहकारिता है : श्री चौहान

कोविड काल में सहकारिता के माध्यम से आपदा नियंत्रण का आदर्श प्रस्तुत किया म.प्र. ने

विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार सृजन होगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान "म.प्र. में सहकारिता आंदोलन : नई ऊर्जा, नई शक्ति और नए क्षितिज" विषय पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहकारिता हमारे संस्कारों एवं संस्कृति में है। हम "सर्वे भवन्तु सुखिन:" तथा "वसुधैव कुटंबकम्" के मार्ग पर चलते हैं। सबके लाभ, सबके कल्याण और सबकी भलाई की सोच ही सहकारिता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने कोविड काल में सहकारिता के माध्यम से आपदा नियंत्रण का आदर्श प्रस्तुत किया। जिला, ब्लॉक, वार्ड एवं ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों ने कोरोना नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहकारिता भगवान की तरह ही सर्वव्यापी है तथा सबका कल्याण करती है। विशेष रूप से छोटे लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। उनके पास बुद्धि, दक्षता, क्षमता तो है पर आर्थिक और अन्य संसाधन नहीं हैं। सहकारिता उन्हें ये सब प्रदान करती है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में "म.प्र. में सहकारिता आंदोलन: नई ऊर्जा, नई शक्ति और नए क्षितिज" विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों के सहकारिता विशेषज्ञ, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सांसद श्री रमाकांत भार्गव, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस आदि उपस्थित थे।

महिला स्व-सहायता समूहों ने उदाहरण प्रस्तुत किया

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों ने सहकारिता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रदेश में इन्हें सशक्त बनाने के लिए 1400 करोड़ रूपए का बैंक ऋण 4% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है।

सहकारिता के माध्यम से अर्थ-व्यवस्था का नवनिर्माण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से अर्थ-व्यवस्था का नवनिर्माण किया जाएगा। पर्यटन, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य-पालन आदि विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता को मजबूत बनाया जाएगा। प्रदेश में सहकारिता 'ग्रोथ का इंजन' बनेगी।

फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में फसलों का बंपर उत्पादन है। यहाँ देश में सर्वाधिक गेहूँ होता है। उद्यानिकी फसलों का भी बहुत उत्पादन है। प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।

"अमूल दूध पीता है इंडिया"

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमूल के निदेशक श्री सोडी से कहा कि 'अमूल' की कमाल की मार्केटिंग है। 'अमूल दूध पीता है इंडिया' गीत मेरी जुबान पर भी है।

"मैं विद्यार्थी हूँ मार्गदर्शक नहीं"

कार्यशाला में जब मुख्यमंत्री श्री चौहान को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने कहा कि "मैं विद्यार्थी हूँ मार्गदर्शक नहीं।" यहाँ सहकारिता के बड़े-बड़े विशेषज्ञ आए हैं, मैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आया हूँ। मैं सभी का आभारी हूँ कि उन्होंने प्रदेश को अपना अमूल्य समय दिया।

सहकारिता आंदोलन को गति मिली है

सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन को गति मिली है। आज की कार्यशाला में आए सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अनुभवों का लाभ सहकारिता आंदोलन को मिलेगा।

बेहतर वातावरण की आवश्यकता

श्री मराठे ने कहा कि भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियाँ पंजीकृत हैं। इनमें से गृह निर्माण संस्थाओं को छोड़कर शेष 4.5 से 5 लाख सहकारी समितियाँ सीधे आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हैं। उन्हें सशक्त करने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में बेहतर वातावरण निर्माण की आवश्यकता है। पर्यटन के क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से आय की अच्छी संभावनाएँ हैं।

सहकारिता को पूंजी की आवश्यकता

आर.बी.आई सेंट्रल बोर्ड के निदेशक श्री सतीश मराठे ने कहा कि आज सहकारिता क्षेत्र में पूंजी की आवश्यकता है। इसके लिए मौजूदा कानूनों में आवश्यक संशोधन करते हुए सहकारी संस्थाओं को अधिक अधिकार संपन्न बनाना आवश्यक है। उन्होंने सहकारिता को सुदृढ़ करने के लिए बेहतर वातावरण निर्माण की आवश्यकता बताई। श्री मराठे ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने में डेयरी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इससे उनकी आय में अच्छी वृद्धि हो सकती है। मध्यप्रदेश में एनिमल सीड बनाने तथा खाद्य प्र-संस्करण की बड़ी संभावनाएँ हैं। मध्यप्रदेश में तिलहन का अच्छा बाजार था। प्रदेश में तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए।

दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर

सहकारिता विशेषज्ञ श्री सुभाष पाण्डे ने कहा कि मध्यप्रदेश डेयरी क्षेत्र में बहुत पीछे था परंतु मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। आज दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में चौथे स्थान पर है।

फसलों का मूल्य गिरने पर भी सहकारिता सबल

कैम्पो के अध्यक्ष श्री किशोर कुमार ने कहा कि सहकारिता फसलों के बाजार मूल्य गिरने पर भी उन्हें सपोर्ट प्रदान करती है। कर्नाटक राज्य में जब लहसुन के दाम गिरे तो सहकारी समितियों ने बड़ी मात्रा में अच्छे मूल्य पर लहसुन खरीदकर किसानों की सहायता की। यह सहकारिता की शक्ति है। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से खेती में तकनीकी के उपयोग पर बल दिया।

सहकारिता छोटे कार्य करने वाले लोगों के लिए है, जो अकेले कुछ नहीं कर सकते

अमूल के क्षेत्रीय निदेशक श्री आर.एस. सोडी ने कहा कि सहकारिता उन छोटे-छोटे कार्य करने वाले व्यवसाइयों और कामगारों के लिए है, जो अकेले कुछ नहीं कर सकते। वे साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। सहकारिता के क्षेत्र को लाभदायक बनाने के लिए इसमें पेशेवर लोगों की सहायता लेनी होगी। आधुनिक तकनीकी का भी उपयोग आवश्यक है। मार्केटिंग और ब्रान्डिंग पर भी ध्यान देना होगा। श्री सोडी ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है और इसके लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान बधाई के पात्र हैं।

किसानों को सहकारिता प्रशिक्षण

सहकारिता विशेषज्ञ श्री डी.डी. त्रिपाठी ने कहा कि किसानों को सहकारिता का प्रशिक्षण देकर उनके कृषक उत्पादन संगठन बनाए जा सकते हैं। स्व-सहायता समूहों एवं किसानों की सहकारी समितियों को कृषि उत्पाद प्र-संस्करण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सहकारिता के क्षेत्र में मानव संसाधन नीति भी बनानी होगी। प्रदेश में कोल्ड चेन, भंडारण को भी बढ़ावा देना होगा।

अधिकतम रोजगार देना मकसद

इंडियन कॉफी वर्कर्स कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी (इंडियन कॉफी हाउस) के श्री एंटोनी ने कहा कि हमारी सहकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम रोजगार देना है। मध्यप्रदेश में अभी हमारी 36 ब्रांच हैं। अब छोटे-छोटे शहरों में भी कॉफी हाउस खोले जा रहे हैं।

0% ब्याज पर ऋण बड़ा कदम

सांसद एवं सहकारिता विशेषज्ञ श्री रमाकांत भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण दिया जाता है तथा ब्याज की राशि सरकार भरती है। यह कृषि एवं सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा कदम है। पूरे प्रदेश में डेयरी एवं मत्स्य-पालन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने आवश्यक

वाशिंगटन डीसी के सहकारिता विशेषज्ञ प्रो. शशिका रवि ने कहा कि मध्यप्रदेश में स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि तकनीकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फसलों की प्रोसेसिंग भी की जाए।

सहकारिता की परिभाषा बताई

सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री विवेक चतुर्वेदी ने सहकारिता की परिभाषा बताते हुए कहा कि जब धन, श्रम एवं बुद्धि तीनों शक्तियाँ एक साथ लगती हैं तो इसका लाभ सभी में बँटता है, वही सहकारिता है। मध्यप्रदेश में श्रमिक सहकारी समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

प्रारंभ में मध्यप्रदेश राज्य योजना एवं नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

श्री तिवारी ने म.प्र. राज्य सहकारी बैंक भोपाल में किया पदभार ग्रहण

भोपाल। सहकारिता विभाग के आदेश के परिपालन में संयुक्त आयुक्त श्री पी.एस. तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के प्रबंध संचालक का पदभार ग्रहण किया।

श्री पी.एस. तिवारी ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश शासन एवं अपेक्स बैंक द्वारा कृषक हितेषी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से किये जाने का अनुरोध किया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।